

बरेली को मिलेगा मंडल का पहला गारमेंट क्लस्टर

साल 2025 बरेली के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इस वर्ष जिले को विकास की कई बड़ी योजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। इन योजनाओं का उद्देश्य बरेली को न केवल आधुनिकता की ओर ले जाना है, बल्कि यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर परिवहन, रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने वाली इन परियोजनाओं से शहर में समग्र विकास होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, तेज और स्मार्ट परिवहन नेटवर्क, रोजगार के बढ़ते अवसर, और उद्योगों के विस्तार से बरेली एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगी। ये परिवर्तन न केवल शहर की छवि को बदलेंगे, बल्कि बरेली को एक समृद्ध और विकसित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे।

5.50
करोड़ से तैयार हुआ गारमेंट क्लस्टर

1000
लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

सौगात

बरेली/मीरगंज। नए साल में बरेली को मंडल का इकलौता रेंडिमेंड गारमेंट क्लस्टर का सौगात मिलेगा। करीब साढ़े पांच करोड़ की लागत से तैयार इस क्लस्टर से एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र का दावा है कि इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन जनवरी माह में कर दिया जाएगा। इसके बाद यहां उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा।

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की लघु सूक्ष्म उद्यम क्लस्टर विकास योजना के तहत यह क्लस्टर मीरगंज तहसील के गांव नौसना में बनकर तैयार हो गया है। इस रेंडिमेंड गारमेंट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण मेसर्स बरेली अट्रैक्स इंटरट्रीड डबलपमेंट सोसायटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेंटर के निर्माण पर केंद्र सरकार 3.72 करोड़, राष्ट्रीय सरकार 1.19 करोड़ एवं मेसर्स बरेली अट्रैक्स इंटरट्रीड डबलपमेंट सोसायटी 73.67 लाख रुपये खर्च कर रही है।

केंद्र सरकार से उसके द्वारा दिए जा रहे अंशदान की 30 लाख रुपयों की धनराशि मिलना शेष रह गई। एमएसएमई की समायोजन रिपोर्ट लगने पर भारत सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अंशदान की शेष धनराशि जारी कर देगा।

सोसायटी के सचिव रिकू मंगवार ने बताया कि धरातल पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोसायटी ने बैंकिंग फैसिलिटी के रूप में 30 लाख की धनराशि जमा कर दी है। एमएसएमई की समायोजन रिपोर्ट लगने पर फैसिलिटी सेंटर में व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो जाएगी।

वर्ष 2017 में स्वीकृत हुई थी परियोजना: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 24 मई 2017 में परियोजना स्वीकृत की थी। सचिव ने बताया परियोजना का फाइनल अप्रूवल 2018 में मिला था। सोसायटी ने 28 मार्च 2021 में परियोजना को पूरा कर दिया।



मीरगंज के गांव नौसना में रेंडिमेंड गारमेंट क्लस्टर बनकर तैयार हो चुका है।

3.62 करोड़ की लगी है आधुनिक मशीनें
फैसिलिटी सेंटर में सोसायटी ने अपनी अंशदान राशि, राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त राशि एवं केंद्र सरकार से अब तक प्राप्त राशि बिलियन, मशीनें लगाने आदि में खर्च कर दी है। सेंटर में 3.62 करोड़ रुपये की मशीनें लगी हैं।

युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण संग रोजगार
सेंटर में गारमेंट की सैकिंग, कटिंग एवं फिनिशिंग की ट्रेनिंग भी बरेलीगंज युवाओं एवं महिलाओं को मिलेगी। सचिव रिकू मंगवार ने बताया फैसिलिटी सेंटर शुरू होने पर क्षेत्र के 1000 बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

जनसहूलियत पर फोकस
उत्पादक बीडीए मनिफेस्टेशन ए ने बताया कि जनता को सहूलियत वाली योजनाओं पर फोकस है। बीडीए सेंटर बरेली, नाथम टाउनशिप, मेट्रो रेत और विकास के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करेगा। जनता के लिए सुविधाओं को पूरा किया जाएगा।

जल्द शुरू होगा उत्पादन
जिला उद्योग केंद्र के उपमुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट में भारत सरकार एमएसएमई आगरा ने कुछ बिंदुओं पर अंशदान मांगे थे, जो दे दिए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल जनवरी में रेंडिमेंड गारमेंट क्लस्टर में उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा।

100 करोड़ रुपये मिलन बरिसर्गों पर होंगे खर्च
■ एक साथ शहर के 80 वार्डों में निर्माण शुरू करने की नगर निगम की है योजना
स्मार्ट सिटी में विकास के गढ़े जाएंगे नए आयाम
मेयर डॉ. उमेश मोहन ने कहा कि साल 2025 शहर के लिए मुक्त होना। स्मार्ट सिटी में विकास के नए आयाम बढ़ें जाएंगे। निगम की ओर 2025 में एक सब 80 वार्डों में निर्माण शुरू करने की योजना है। सभी मिलन बरिसर्ग 100 करोड़ से पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी।

मेयर डॉ. उमेश मोहन ने कहा कि साल 2025 शहर के लिए मुक्त होना। स्मार्ट सिटी में विकास के नए आयाम बढ़ें जाएंगे। निगम की ओर 2025 में एक सब 80 वार्डों में निर्माण शुरू करने की योजना है। सभी मिलन बरिसर्ग 100 करोड़ से पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी।

100 बेड का यूनानी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, उद्घाटन का इंतजार

विक्रित

बरेली, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश सरकार के डीएम प्रोजेक्ट में शामिल यूनानी मेडिकल कॉलेज का तोहफा नए साल में मिलेगा। यूनानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया है। मेडिकल कॉलेज में यूनानी पैथी से उपचार करने वाले डॉक्टर भी तैयार किए जाएंगे। बरेली के साथ-साथ रुहेलखंड और उत्तराखंड के मरीजों को भी मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा। स्टेडियम रोड स्थित हजियापुर में नगर निगम की 27 हजार वर्ग मीटर जमीन पर



यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। 113 करोड़ की एकम खर्च कर तीन महीने पहले बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। सिर्फ बिजली कनेक्शन की वजह से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो सका। कॉलेज तक स्पेशल फीडर से अंडर ग्राउंड लाइन बिछाने की बात करोड़ के बजट की जरूरत है। पीटब्ल्यूटी व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के सहमति बन गई है।

बोले जिम्मेदार

कनेक्टिविटी होगी बेहतर

नगरपालिका सचिव मोहन ने बताया कि जनता से जुड़े काम सफल रहेंगे। कनेक्टिविटी के मामले में बरेली 2025 में विकास प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर 2025 में काम होने जा रहा है।



जिले को मिलेंगे 25 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र

सीएमओ डॉ. विभूष सिंह ने बताया कि शहर में 5, बहेरी में 8, वाराणसी में एक, भगवत में 2, भोजपुर में 2, मधुबनी में 1, मुंडा नदी बहा में 2 व फतेहगढ़ एरिजमी में 1 स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे।



रेलवे की बदलेगी तस्वीर

जखन पर खुलेगा रेल कोव रेस्टोरेंट बरेली जंक्शन पर कॉन्फिडेंस विभाग की ओर से रेल कोव रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिससे रेलवे की तस्वीर मिल गई है। बरेली जंक्शन के सुक्रेडिटिंग परियोजना में अंतिम तक रेल

कोव रेस्टोरेंट खुलने की उम्मीद है। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बताया जा रहा है कि नामित एजेंसी को रेलवे कोव उपकरण कराई जाएंगे। एजेंसी उन कोव से रेस्टोरेंट बनाएगी, जहां 24 घंटे सस्ता और शुद्ध शाकाहारी भोजन और नारत मिलेगा।

शुरू होगा इंसुलिन केंद्र किसानों को मिलेगा लाभ

डेलीयर तिन्हें पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से इंसुलिन सेंटर बनकर तैयार है। एक करोड़ रुपये की लागत से बिल्डिंग बनाने के साथ यहां एक करोड़ 80 लाख की मशीनें लवाई जानी है, जो

अने लगी है। कार्यालय आरंभिक के मुताबिक 15 जनवरी के बाद सभी भी यह शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी मंडी में कई बार दाम उछल न मिलने पर किसानों को मजदूर अपनी फसल को फैकन पड़त था। जनवरी 2025 से अब किसानों को टमटोर जैसी फसल को सड़क पर नहीं फैकन होगा, बल्कि उसी लेकर बैच सड़कें या उससे सौंल बचवा सके।

